कलम का सौदा

हिन्दी साप्ताहिक

राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

www.kksnews.com

वर्ष 16 अंक 47 हरिद्वार 16 जुलाई 2022 डाक पंजीयन संख्या: UA/DO/DDN/275/2015-2017 R.N.I. No. UTTHIN/2006/17725 मूल्य 1रुपया पृष्ठ 4

कांवड़ मेला शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएं: सीएम

-मुख्यमंत्री ने की कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा

देहरादून (सू. वि.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सी.सी.आर हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कांवड़ मेला शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएं। सकुशल कांवड़ मेला सम्पन्न कराने के लिए कांवड़ मेले से संबधित अन्य राज्यों के अधिकारियों से भी निरन्तर समन्वय बनाकर रखें। यह सुनिश्चित किया जाए कि 14 जुलाई से 26 जुलाई 2022 तक होने वाले कांवड़ मेले में स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अच्छी हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा में 04 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने सभी शिवभक्तों से अपील की कि देवभूमि उत्तराखण्ड में कांवड़ यात्रा पर आने वाले शिवभक्त एक-एक पौधा लगाएं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिये कि कांवड़ यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिलास्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत जो एडवाइजरी बनाई गई है, उसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान निर्देश दिये कि कांवड़ मेले में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, जिनकी कोविड की बूस्टर डोज नहीं लगी है, उनकी बूस्टर डोज लगवाई जाए।

कांवड़ यात्रा सुव्यवस्थित हो इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं कांवड़ मेले से संबंधित जिलों के अधिकारी शामिल किये जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ मेला अवधि में हरिद्वार में कांवड़ मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पार्किंग स्थलों में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था रखी जाए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर शाइनेज की पूर्ण व्यवस्था हो। कांवड़ पटरी पर विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था हो। वन क्षेत्र में जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु चेतावनी बोर्ड लगाये जाएं। कांवड़ मेला के दौरान यात्रा रूटों का पूरा चार्ट दिया जाए। भण्डारे एवं लंगर के लिए हाइवे से दूरी पर स्थान चिन्हित किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ मेले के दौरान पर्वतीय जनपदों में आवश्यक सेवाओं एवं सामग्रियों को भेजने के लिए कोई परेशानी न हो। होटलों एवं दुकानों में रेट लिस्ट चस्पा की जाए। स्थानीय स्तर पर लोगों को आवागमन में अधिक जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पाण्डेय ने कांवड़ की तैयारियों को लेकर प्रस्तुतीकरण देते हुए कहा कि कांवड़ मेले के लिए 60 हजार वाहनों की क्षमता के लिए 13 पार्किंग स्थल बनाये गये हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों के लिए 03 अतिरिक्त पार्किंग स्थल आरक्षित हैं। कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन हेतु मेला क्षेत्र में 12 सुपर जोन, 32 जोन एवं 134 सेक्टर बनाये गये हैं। सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में 17 अस्थाई स्वास्थ्य शिविरों की स्थापना की गई है। चिकित्सा केन्द्रों में एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक प्रदीप बत्रा, आदेश चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, एडीजीपी डॉ. वी मुरूगेशन, सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम एवं जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम समीक्षा बैठक लेते हुए।

उत्तराखंड को कर्ज से उबारने को सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन

देहरादून (सू. वि.)। उत्तराखंड को कर्ज से उभारने को सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन प्लान बना है। धामी ने साफतौर से कहा कि फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने देहरादून में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन प्राइवेट होटल और निजी स्थानों पर करवाने की रोक लगा दी। सीएम ने मुख्य सचिव एसएस संधू को निर्देश दिए हैं।

सीएम ने कहा कि इस प्रकार के सभी कार्यक्रम सीएम कैंप आफिस के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किए जाएं। इसीप्रकार की व्यवस्था जिला स्तर पर भी लागू करने को कहा गया है। सीएम के इस फैसले को आर्थिक अनुशासन की ओर बढ़ते कदम की तरह देखा जा रहा है। दरअसल, इस महीने से राज्य को जीएसटी के रूप में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी खर्चे को कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए मैंने राजधानी में होटल या अन्य निजी स्थानों पर आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

को मुख्यसेवक सदन में आयोजित किए जाने हेतु मुख्य सचिव को निर्देशित किया है साथ ही सभी जनपदों में भी यही कार्यप्रणाली लागू करने के लिए कहा है।

75 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा है उत्तराखंड

उत्तराखंड इस वक्त बड़े कर्ज के बोझ के तल दबा हुआ है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक राज्य पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका था। इस हिसाब से राज्य का प्रत्येक व्यक्ति पर 65 हजार रुपये का कर्जदार है। राजस्व के ठोस स्रोत न होने की वजह से कर्ज की राशि लगातार बढ़ती जा रही है।

सरकारी खर्चे को कम करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। मैंने राजधानी में होटल या अन्य निजी स्थानों पर आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों को मुख्यसेवक सदन में आयोजित किए जाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया है। किया है। साथ ही सभी जनपदों में भी यही कार्यप्रणाली लागू करने के लिए कहा है।

उत्तराखंड में भयावह होता कोरोना, आज मिले 67 केस

देहरादून (संवाददाता)। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर तेजी से इजाफा शुरू हो गया है। राज्य में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को मरीजों की संख्या में तकरीबन पचास फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 47 नए मरीज मिले थे। जबकि शनिवार को राज्य में कोरोना के 67 नए मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण दर में भी इजाफा हो रहा है। एक ही दिन में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने की वजह से राज्य में कोरोना संक्रमण की दर भी अचानक बढ़कर 4.26 प्रतिशत पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभगा की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को 31 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। इसके बाद अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 361 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून में सर्वाधिक 43 नए मरीज मिले हैं।

न्यूज अपडेट्स

बायोमेट्रिक के जरिए खाते से निकल गए 90 हजार

देहरादून (संवाददाता)। बायोमेट्रिक के जरिए बैंक खाते से 90 हजार रुपये निकल गए। खाते से रकम निकलने को लेकर मनीष कुमार निवासी विजय पार्क ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तहरीर दी। कहा कि उनके बैंक खाते से 30 जून को बायोमेट्रिक के जरिए 90 हजार रुपये निकलने के मैसेज आए। इसके बाद उन्होंने आधार से बायोमेट्रिक सिस्टम लॉक कर दिया। साइबर थाने में दी गई तहरीर वसंत विहार थाने पहुंची। थानाध्यक्ष विनोद राणा ने बताया कि तहरीर पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

ओटी तकनीशियन को प्लाट दिलाने की डील कर 4.71 लाख हड़पे

देहरादून (संवाददाता)। निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के तकनीशियन को कोल्हूपानी, प्रेमनगर में जमीन दिलाने की डील कर 4.71 लाख रुपये हड़प लिए गए। धोखाधड़ी को लेकर हरीश चंद्र हाल निवासी चंद्रलोक कॉलोनी दिलाराम ने तहरीर दी। कहा कि विकास कुमार कसाना निवासी किशनपुर और अमरजीत समरा निवासी शिवालिक अपार्टमेंट कैनाल रोड ने प्लाट दिलाने की डील की। 16 सितंबर 2021 को प्लाट का एग्रीमेंट हो गया। पीड़ित ने एडवांस 4.71 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। आरोप है कि इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। पीड़ित को बाद में पता लगा कि आरोपियों ने फर्जी दस्तोजव दिखाकर उससे रकम ली। प्रेमनगर थानाध्यक्ष दीपक रावत ने बताया कि तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

दो अवैध कॉलोनियों को सीज किया

हरिद्वार (संवाददाता)। एचआरडीए के अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफअभियान चलाते हुए आन्नेकी हेतमपुर में दो अवैध कॉलोनियों को सीज कर दिया है। एचआरडीए के अधिशासी अभियंता माधवानंद जोशी ने बताया कि आन्नेकी हेतमपुर में राजवीर सिंह की ओर से की जा रही अवैध प्लॉटिंग और इंद्रजीत अरोड़ा की ओर से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को सीज कर दिया गया है।

सम्पादकीय

जिम्मेदार नागरिकों को आगे आना होगा

दरअसल, वनों संक्षरण को लेकर दुनिया में कोई ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं हुआ है जो आमजन और सरकारों को वनों की कटाई रोकने के लिए विवश करता हो। भारत सहित दुनिया के कुछ ही देशों में वन कटाई को रोकने के लिए समय–समय पर आंचलिक आंदोलन चलाए गए। भारत में उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में वन संरक्षण के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए गए और उनमें सफलता भी मिली। लेकिन जिन वजहों से जंगलों की अंधाधुंध कटाई जारी है, उन्हें खत्म नहीं किया जा सका है। वन संरक्षण को लेकर यही बड़ी मुश्किल है। यह समझना होगा कि विकासशील देशों के लिए जंगल एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं।वनों की कटाई से वनभूमि की कमी ही नहीं हो रही, बल्कि जैविक विविधता भी धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है। महत्त्वपूर्ण वनस्पतियों, औषधियों व जीव–जंतुओं के लुप्त होने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ग्लासगो में वन कटाई को लेकर जो समझौता हुआ है, वैसा ही समझौता 2014 में न्यूयार्क घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले चालीस देशों ने किया था। इसके अनुसार 2020 तक जंगलों की कटाई को पचास फीसद तक रोकना था। लेकिन इस पर अमल ही नहीं किया गया। ग्लासगो सम्मेलन में हुए समझौते पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बयान में कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन या जंगलों की कटाई के नाम पर जारी विकास रुकना नहीं चाहिए। निश्चित ही ऐसे बयानों से वनों की कटाई पर रोक लगाने में मदद नहीं मिलेगी और इससे घोषणापत्र में प्रदर्शित सामूहिक इच्छाशक्ति के पालन में कमजोरी आएगी।भारत ने इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करके यह बता दिया है कि वह वनों की कटाई रोकने के लिए प्रतिबद्ध तो है ही, साथ ही वन क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर भी उसकी ईमानदार सोच है। इसलिए जंगलों को बचाने ते लिए भारत सहित उन सभी देशों को तत्काल ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे जिससे पर्यावरण, जैव विविधता, औषध सुरक्षा और जीव–जंतुओं की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित हो सके। इससे जहां कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही खतरनाक समस्याओं का हल खोजने में मदद मिलेगी, वहीं वनों के सहारे जीवनयापन करने वाले लोगों की भी सुरक्षा हो सकेगी। जरूरत इस बात की है कि विश्व स्तर पर जितनी मजबूती के साथ सरकारें वन सुरक्षा के लिए कदम उठाती हैं, उतनी ही जिम्मेदारी से जिम्मेदार नागरिकों को आगे आना होगा। तभी जगल बच पाएंगे।लेकिन इतने भर से बात नहीं बनने वाली। भारत में जिस तेजी से वनस्पतियां विलुप्त हो रही हैं, उससे लगता नहीं कि केंद्र सरकार कुछ कानूनों के जरिए भी उनकी पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी। गौरतलब है जंगलों की कटाई और इसी से जुड़ा वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त होने का मुद्दा कोई सामान्य बात नहीं है।यह जैविक विविधता, औषध सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा–सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।

'नूपुर' की झँकार 'सुप्रीम' के प्रति 'सुप्रीम' की नाराजी....!

ओमप्रकाश मेहता

देश पर राज कर रही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया वही बयान उनकी जगह किसी ओर द्वारा दिया गया होता तो क्या वह नूपुर की तरह महफूज रह पाता? बयान का चौतरफा विरोध होने पर भाजपा ने फौरी कार्यवाही कर नूपुर को प्रवक्ता पद से हटा दिया, किंतु क्या उनकी गिरफ्तारी हुई, जबकि उनके इस बयान से बकौल सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में आग लग गई यही नहीं उनके उस बयान के एक समर्थक की राजस्थान के उदयपुर में नृशंस हत्या तक कर दी गई, आखिर ऐसे खतरनाक माहौल को देखकर देश की सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप कर नूपुर शर्मा तथा उनके विवादित बयान की निन्दा करनी पड़ी, किंतु इस सबके बावजूद केन्द्र सरकार अभी भी मौन है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस माहौल के लिए केन्द्र को भी दोषी ठहराया है।

भाजपा की इस नैत्री के इस बयान के बावजूद दिल्ली में उनके खिलाफकोई मामला तब तक दर्ज नही किया गया, जब तक कि इस मामले में केन्द्र के अधीन दिल्ली पुलिस पर कोई दबाव नहीं आया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर एक याचिका कीक बहस के दौरान जब नूपुर के वकील ने कहा कि– ''नूपुर की जान को खतरा है'', तो माननीय न्यायमूर्ति का कहना था कि नूपुर की जान को खतरा नहीं, बल्कि नूपुर स्वयं देश के लिए खतरा है, न्यायालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा उसके खिलाफअब तक कोई कार्यवाही नहीं करने पर केन्द्र सरकार को भी आरोपी के कटघरे में खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर को निर्देश दिए कि वे टीव्ही चौनलों पर जाकर अपने इस बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगें, वह भी बिना किसी शर्त के। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली को छोड़ देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में नूपुर के खिलाफकेस दर्ज हुए है और वे खेद व्यक्त करने के बजाय अभी भी ये सभी केस दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग कर रही है और उसकी वजह अपनी जान का खतरा बता रही है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय इस मांग से सम्बंधित नूपुर की याचिका को खारिज कर चुकी है।

अब यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्र की मोदी सरकार कई मामलों के कारण विवादित होती जा रही है, फिर वह चाहे अग्निपथ योजना का मामला हो या कि इससे पूर्व की समान नागरिक संहिता या बुर्का प्रथा बंद करने के प्रयास हो, मोदी सरकार के और भी कुछ ऐसे कदम है जिनके कारण देश में साम्प्रदायिक विवाद बढ़ते जा रहे है। देश के एक वरिष्ठ राजनायिक ने ठीक ही कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार आए दिए नए–नए विवादों में फंस कर अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है इस सरकार ने पिछले कुछ महीनों में जितनी भी योजनाएं देश के सामने पेश की वे सभी देश के लिए 'घाटे का सौदा' सिद्ध हुई। हाल ही में कुछ अखबारों में छपा है कि सीएए, किसान, अग्निपथ तथा नूपुर प्रसंग के कारण हुई हिंसा–आगजनी आदि से देश को 646 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है और इन्ही वारदातों के कारण तथा सरकार के हर फैसले के विरोध के कारण ग्लोबल पीस इण्डेक्स (विश्व शांति सूची) में भारत 163 देशों की सूची में 135वें स्थान पर आ गया है और भारत के जीडीपी का 6 फीसदी हिस्सा हिंसा की आग में भस्म हो रहा है, किंतु भारत को इसकी कोई विशेष चिंता नही है? यदि यह चलता रहा तो भारत अफगानिस्तान को पीछे छोड़ पूरे विश्व के हिंसा वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगा। जबकि आज यह कोई सोचने को तैयार नहीं है कि हिंसा ही आज विकास की सबसे बड़ी बाधा है।

इस तरह कुल मिलाकर यदि यह कहा जाए कि केवल राज्य या विधायिका के चुनाव जीत जाने से लोकप्रियता बढ़ती है? यह गलत है इसके लिए सरकार को जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी, क्योंकि अब देश की आजादी के पचहत्तर साल बाद देश का आम वोटर शिक्षित व जागरूक हो गया है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है इसलिए समय रहते राजनीति को सही पथ की पहचान कर लेनी चाहिए।

शिष्य बना प्रशंसा का पात्र

गंगा किनारे गुरु अभेंद्र का आश्रम था। एक बार देश में भीषण अकाल पड़ा। गुरु अभेंद्र ने संकटग्रस्तों की मदद के उद्देश्य से अपने तीन शिष्यों को बुलाकर कहा – ऐसे संकट के समय में हमें अकाल पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। तुम लोग अलग–अलग क्षेत्रों में जाकर भूखों को भोजन कराओ।

उनकी बात सुनकर शिष्य बोले – गुरुजी, हम इतने सारे लोगों को भोजन कैसे कराएंगे? हमारे पास न तो अन्न भंडार है और न अनाज खरीदने के लिए धन। तब गुरु अभेंद्र ने उन्हें एक थाली देते हुए कहा – यह थाली दिव्य है। तुम जितना भोजन मांगोगे, यह उतना भोजन उपलब्ध कराएगी। तीनों शिष्य थाली लेकर निकल पड़े। दो शिष्य एक स्थान पर बैठ गए। उधर से जो भी गुजरता, उसे वे भोजन कराते। किंतु तीसरा शिष्य मोहन बैठा नहीं, बल्कि घूम–घूमकर भूखों को खोजता रहा और उन्हें खाना बांटता रहा। कुछ दिनों बाद जब तीनों आश्रम लौटे, तो गुरु ने मोहन की खूब प्रशंसा की। दोनों शिष्यों को यह अजीब लगा।

उन्होंने पूछा – गुरुदेव, हमने भी तो अकाल पीड़ितों की सेवा की है। फिर मोहन की ही प्रशंसा क्यों गुरु ने उत्तार दिया – तुमने एक ही स्थान पर बैठकर पीडघ्तों की सहायता की। ऐसा करने से वे लोग तुम्हारी मदद से वंचित रह गए, जो चलकर तुम्हारे पास आने में असमर्थ थे। जबकि मोहन ने लोगों के पास जा–जाकर उन्हें भोजन कराया। उसकी सहायता अधिकतम लोगों तक पहुंची, इसलिए उसकी सेवा अधिक प्रशंसा के योग्य है। कथा का सार यह है कि वही सेवा अधिक सराहनीय होती है, जो आगे बढ़कर की जाए।

सत्ता की सियासत में गड़बड़ाया आर्थिक समीकरण

सनत कुमार जैन

भारत की अर्थ व्यवस्था और मंदी को लेकर रिर्जव बैंक की ताजा रिपोर्ट ने अर्थ – विशेषज्ञों को गंभीर चिंता में डाल दिया है। सरकार भी इस स्थिति से निपटने के लिए फौरी प्रयास कर रही है। उससे अर्थ – व्यवस्था और बिगड़ रही है। मंहगाई, बेरोजगारी, कर्ज, बढ़े हुए टेक्स एवं शुल्क को लेकर आम कर्ज के बोझ से जनता कराह रही है। 2014 में अच्छे दिन के नारे से केन्द्र में नई सरकार आई है। 2014 में जो अर्थ – व्यवस्था थी। उसमें बेहतर तो नहीं हुआ, उल्टे 2022 तक भारत की आर्थिक स्थिति बद से बदहाल हो गई है। 2014 में भारत का अर्न्तराष्ट्रीय कर्ज 55 लाख करोड़ रूपये था जो अब बढकर 133 लाख करोड़ रुपया हो गया है। सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से भारी कर्ज लिया है। जीएसटी के दायरे में गरीब और अमीर सभी आ गए हैं। जीएसटी का दायरे में सामान, सेवाओं यहॉ तक की बैंकिंग एवं कर्ज को भी जीएसटी के दायरे में लाकर गरीबों पर भी भारी टेक्स लगाया गया है। इसके बाद भी अर्थ – व्यवस्था सुधरने के स्थान दिबालिया होने की कगार पर पंहुच रही है।

– अर्न्तराष्ट्रीय कर्ज

2014 में भारत के उपर अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं का कर्ज 53 लाख करोड़ था। जून 2022 में यह बढकर 133 लाख करोड़ रुपया हो गया है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में मार्च 2023 तक विदेशी कर्ज बढकर 153 लाख करोड़ होने का अनुमान है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कर्ज का यह बोझ अकल्पनीय है। आर्थिक मंदी के दौर में कर्ज पर ब्याज के बोझ से आम जनता को राहत देने वाली योजनाओं को लागू रख पाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है।

विदेशी निवेश घटा

वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में अमेरिका ने जैसी ही अपनी ब्याज दरें बढ़ाई। विदेशी निवेशक भारत से अपना निवेश निकालकर अमेरिका एवं अन्य देशों पर निवेश कर रहे हैं। परिणाम स्वरुप भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का जो दौर शुरू हुआ है। वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विदेशी निवेशकों ने पिछले 6 माह में भारतीय बाजार से 2 लाख 18 हजार करोड़ का विदेशी निवेश निकाल लिया है। बाजार में गिराबट एवं आर्थिक मंदी के कारण भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के लिए लाभकारी नहीं रहे। वहीं भारत में अनका निवेश भी सुरक्षित नहीं रह गया। मौजूदा स्थिति भारत की आर्थिक स्थिति को विष्फोटक बना रही है।

मंहगाई और बेरोजगारी –

भारत में पिछले दो वर्षों से मंहगाई लगातार बढ रही है। मंहगाई पर लगाम लगाने में सरकार असफल रही है। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और मंहगाई के कारण आम आदमी पर कर्ज का बोझ लगातार बढ रहा है। आर्थिक संकट के कारण हजारों कारोबारियों एवं औद्योगिक समूहों ने दिबालिया घोषित कर कर्ज से पल्ला झाड़ लिया है। बैंकों की बेलेन्सशीट बेहतर बनाए रखने के लिए बैंकों के विलय और सार्वजनिक कम्पनियों के निजीकरण के बाद भी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है।

–गरीवों की योजनाओं पर कटौती –

केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में बजट में सब्सिटी को काफी घटा दिया है। मनरेगा में पिछले वर्ष 98 हजार करोड़ का बजट था। जिसे घटाकर सरकार ने 73 लाख करोड़ कर दिया गया। आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना , स्वास्थ्य का बजट भी कम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास उज्जवला योजना का बजट 1618 करोण से घटाकर 800 करोण रुपया कर दिया। खाद की सब्सिडी 25 फीसदी कम हो गई है। अनाज की सब्सिडी घटा दी गई है। जीएसटी में 6 स्लेब और टेक्स के दायरे को तेजी से बढ़ाया गया। उसके बाद भी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

2014 के बाद से केंद्र सरकार ने अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नोटबंदी, जीएसटी, सब्सिडी घटाने, टेक्स एवं शुल्कों में वृद्धि, जीएसटी के दायरे में सभी सेवाओं और गुड्स को शामिल करने, पेट्रोल–डीजल पर टेक्स बढ़ाकर सरकार ने अपनी आय तो बढ़ाई है। किन्तु इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होने के स्थान पर साल–दर–साल खराब होती जा रही है।

नई सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण सरकारी धन और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे कारपोरेट जगत को मिल रहा है। जिसके कारण मध्यम वर्ग एवं कमजोर वर्ग की कमाई कम होती चली गई। इन पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। कारपोरेट टेक्स घटा, वहीं कारपोरेट की आय तेजी से बढ़ी। अमीरी और गरीबी के बीच तेजी से असमानता बढ़ रही है। वहीं महंगाई एवं बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है।

–2008 और 2023 की आर्थिक मंदी ?

2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत पर विशेष असर नहीं पड़ा था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक मंदी से निपटने की सराहना की थी। उस समय

भारत की कृषि आय और अनअर्गगाइजड सेक्टर की आर्थिकी ने भारत की अर्थ व्यवस्था को मजबूत बना रखा था। 2014 के बाद विदेशी निवेशकों के लिए 100 फीसदी विदेशी निवेश की स्वीकृति देकर खुदा व्यापार, रक्षा, बैकिंग मीडिया इत्यादी को भी कारपोरेट के हवाले कर दिया गया। सरकार की नीतियों कारपोरेट हितों को बजबूत बनाने वाली है। इससे भारत के छोटे कारोबारी एवं मध्यम वर्ग को बडा नुकसान हुआ है। सारा फायदा सीधे कारपोरेट को मिल रहा है।

आवास योजना व अमृत सरोवर निर्माण कार्यों की सीडीओ ने की समीक्षा

रूद्रपुर। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में मनरेगा, पीएम आवास योजना ग्रामीण, अमृत सरोवर निर्माण कार्यों की गहनता से समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमित्ता न हो, निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता तथा सयमबद्धता से पूरे किये जाये। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का चयन पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता से किया जाये और संचालित योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुॅचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि योजनाओं का क्रियान्वय पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता व समयबद्धता से किया जाये ताकि योजनाओं का लाभ समय से पात्र व्यक्तियों को मिल सके। उन्होंने राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर पर शतप्रतिशत मस्टरोल ऑनलाइन करने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारियों को दिये। उन्होंने नियमानुसार सोशल ऑडिट कराने के निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिये। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक से पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अच्छा आवास निर्माण कराने वाले 5-5 भवन स्वामियों को पुरस्कृत किया जायेगा। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि क्षेत्रों के चहुॅमुखी विकास और अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुॅचाने के लिए आपसी समन्वय से सामूहिक प्रयास किये जाये।

मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत जनपद में 76 तालाबों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा करने के सख्त निर्देश सभी खण्ड विकास अधिकारियों व डीपीओ को दिये। उन्होंने परिस्थितियों की सरलता के आधार पर जनपद में कम से कम 45 तालाब निर्माण कार्य 30 जुलाई तक पूरा करने के कड़े निर्देश खण्ड विकास अधिकारियों को दिये।

सीडीओ समीक्षा बैठक लेते हुए।

उन्होंने अमृत सरोवर निर्माण कार्य में प्रगति लाने हेतु प्रत्येक अमृत सरोवर के लिए नोडल कार्मिक नियुक्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने मिट्टी का निस्तारण नियमानुसार करने के भी निर्देश सभी खण्ड विकास अधिकारियों को दिये।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिये कि भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाये तथा निर्माण कार्यों को समय से जियो टेग किया जाये ताकि अगली किश्त समय से जारी की जा सके। उन्होंने अपने-अपने विकास खण्डों में आवास पूर्ण कराने हेतु सूक्ष्म कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन आवास निर्माण कार्यों मे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, उन्हें जल्दी पूरा कराया जाये। उन्होंने आवास निर्माण कार्यों की तीन दिन बाद पुन: समीक्षा बैठक आयोजित कराने के निर्देश परियोजना प्रबन्धक को दिये।

इसके साथ ही कार्यों की जियोटेगिंग, सोशल ऑडिट, एटीआर अपलोडिंग, लेबर मटेरियल अनुपात, आधार सीडिंग, आजीविका पैकेज मॉडल, लाइवलीहुड कलस्टर आदि की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में पीडी डीआरडीए हिमांशु जोशी, जिला विकास अधिकारी तारा ह्यांकी, खण्ड विकास अधिकारी सुरेश चन्द पन्त, गंगा गिरी गोस्वामी, शेखर चन्द्र जोशी, असीत आनन्द, नवीन चन्द्र उपाध्याय, चिन्ताराम आर्य, प्रेम सिंह डसीला सहित डीपीओ आदि उपस्थित थे।

कावंड़ मेले में लगने वाले अस्थाई चिकित्सा केन्द्रों का डीजी हेल्थ ने किया निरीक्षण

हरिद्वार (संवाददाता)। कांवड़ मेले को लेकर शुक्रवार को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की महानिदेशक डॉ. शैलजा भट्ट और अपर निदेशक उपचार डॉ. उमा शंकर कण्डवाल ने कावंड़ मेले में लगने वाले अस्थाई चिकित्सा केन्द्रों के स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेला अस्पताल में बने स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर कांवड़ियों के साथ मधुर व्यवहार करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएमओ डॉ. कुमार खगेन्द्र सिंह और कांवड़ के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश गुप्ता से मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

डॉ. शैलजा भट्ट ने कहा कि कांवड़ मेले में करीब चार करोड़ कांवडियों के आगमन का अनुमान लगाया जा रहा है। जिसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। अस्थाई चिकित्सा केन्द्रों में तैनात चिकित्सकों, फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वॉय को भी कांवड़ियों के साथ मधुर व्यवहार करते हुए उपचार करने के निर्देश दिए। अपर निदेशक डॉ. उमा शंकर कण्डवाल ने कहा कि कांवड़ मेले में स्वास्थ्य विभाग को एक टीम की तरह काम करना है। उन्होंने नोडल अधिकारी को प्रतिदिन अस्थाई चिकित्सा केन्द्रों से सम्पर्क कर तैनात चिकित्सकों से रोजाना केन्द्र में पहुंचने वाले मरीजों के संबंध में रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए। चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. शैलजा भट्ट, निदेशक डॉ. उमा शंकर कण्डवाल के साथ निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉ. खगेन्द्र सिंह, नोडल अधिकारी डॉ. राजेशगुप्ता, सहायक नोडल अधिकारी डॉ. तरुण मिश्रा, स्वास्थ्य शिक्षक बीके गुप्ता, माइक्रोबाइलोजिस्ट डॉ. निशात अंजूम, डॉ. तेजिस्वेता बिष्ट, डॉ. वैभव कोहली, डॉ. नलिंद असवाल, डॉ. करिश्मा, अनीता शर्मा, अंशु तोमर, अशोक कालरा, इब्राहिम, मयंक, सुशील, हिमानी, सलमा आदि मौजूद रहे।

रिटायर पुलिस अफसरों ने टोल प्लाजा पर मांगी छूट

देहरादून (संवाददाता)। पीपीएस (रिटायर्ड) ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी कल्याणकारी कार्यों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से मिले। सीएम से उत्तराखंड में स्थित टोल बैरियरों पर पुलिस पेंशनर्स को कार्ड दिखाने पर टैक्स से छूट प्रदान करने की मांग की। पीपीएस (रिटायर्ड) ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय एवं सभागार के लिए एक बीघा भूमि आवंटित करने के लिए पत्र सौंपा। पुलिस के वर्ष 2001 और 2002 के भर्ती कांस्टेबलों को 4600 ग्रेट पे की घोषणा के अनुरूप शासनादेश जारी करने के संबंधित पत्र दिया। सीएम ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस दौरान ज्ञापन में अध्यक्ष जीसी पंत, उपाध्यक्ष बीबीडी जुयाल व जेसी उपाध्याय, महासचिव श्रीधर प्रसाद बडोला, सचिव शिवराज सिंह यादव, दिनेश चंद्र तिवारी आदि शामिल रहे।

नेहरुग्राम एसजीआरआर के छात्रों ने तैयार किए बीज बम

देहरादून (संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में हुए बीज बम अभियान सप्ताह कार्यक्रम से जूम लिंक से एसजीआरआर इंटर कालेज नेहरुग्राम के छात्र-छात्राओं को भी जोड़ा गया। स्कूली बच्चों को खुद मुख्यमंत्री व बीज बम अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भावी पीढी को धरती के वास्तविक श्रृंगार, पेड पौधों की रक्षा के लिए सचेत होना होगा। यह एक नवीन जन आंदोलन की शुरूआत है।

राइजिंग उत्तराखंड प्रदर्शनी को सराहा

देहरादून (संवाददाता)। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेगा एग्जिबिशन का आयोजन किया गया। 'राइजिंग उत्तराखंड थीम पर आधारित प्रदर्शनी का समापन पैसेफिक होटल में हुआ। अंतिम दिन लोगों में उत्साह देखने को मिला।

कार ने पैदल चल रहे व्यक्ति को मारी टक्कर, मौत

हल्द्वानी (संवाददाता)। जोगीपुरा में तेज रफ़्तार कार ने पैदल चल रहे एक मजदूर को टककर मार दी। हादसा इतना भयानक था मजदूर बुरी तरह घायल हो गया। जिसके बाद उसके साथ ने घायल को संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मजदूर के मौत मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर वाहन चालक के खिलाफमुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार को खोड़ा रामपुर निवासी रनवीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह मजूदरी का कार्य करता है। बताया कि बीती देर रात वह खोड़ा निवासी विकास पुत्र विक्रम सिंह समेत कुछ अन्य साथियों के साथ जोगीपुरा की ओर जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार कार चालक अरुण ने विकास को जोरदार टककर मार दी। जिसके चलते विकास की मौत हो गयीद्य कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि तहरीर के आधार पर वाहन चालक के खिलाफमुकदमा दर्ज किया गया है।

भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी बैठक 11 जुलाई को

देहरादून (संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारियो की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में 11 जुलाई सोमवार को अपराह्न 2 बजे भाजपा मुख्यालय में आयोजित होगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में उत्तराखण्ड प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय का मर्गदर्शन प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, सभी ज़िला अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे।

मिट्टी बचाने को जागरूकता कार्यक्रम

देहरादून (संवाददाता)। राजपुर रोड पेसेफिक मॉल में मिट्टी बचाओ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ईशा फाउंडेशन के प्रवर्तक सद्गुरू जग्गी वासुदेव ने कोयंबत्तूर से 24 जून को मिट्टी बचाओ के बारे में शहर-शहर जागरूकता फैलाने के लिए बाइकर्स को रवाना किया था। बाइकर्स का देहरादून में पहुंचने पर ढोल दमौ के साथ स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि पेड़ लगाए जाने के साथ-साथ उनके देखभाल भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मिट्टी बचाओ की मुहिम को साथ हमेशा रहेगा। कार्यक्रम का आयोजन ईशा स्वयंसेवकों, मिट्टी बचाओ समर्थकों, इनर व्हील और हिमवंत फाउंडेशन संस्था के सहयोग से किया गया। सोमेन, अर्चना रतूड़ी, निशांत वैश्य, संगीता थपलियाल, सुशांत मोहन, नंदिता, नीति आदि मौजूद रहे।

आबकारी विभाग मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन के दीपक कुमार अध्यक्ष, अमित महामंत्री

देहरादून (संवाददाता)। आबकारी विभाग मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की सातवीं कार्यकारिणी का गठन शनिवार को किया गया। आबकारी मुख्यालय के बैठक हॉल में कर्मचारियों की मांगें भी उठाई गई।दीपक कुमार अध्यक्ष, विनोद कुमार उपाध्यक्ष, अमित रावत महामंत्री, ललिता प्रसाद रतूड़ी कोषाध्यक्ष, समरवीर सिंह बिष्ट व अभिलाषा डोभाल संगठन मंत्री, सोनाली, हिमांशी प्रचार मंत्री, जितेंद्र सिंह राणा विधि सलाहकार, अनिल कुमार ध्यानी मीडिया प्रभारी बनाए गए। सोबन सिंह नेगी और सैयद रजा वसी जाफरी को संरक्षक मनोनित किया गया। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। लिपित संवर्ग के लिए पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की मांग उठाई गई। इस दौरान सहायक लेखाकारों की नियुक्ति होने पर जिला आबकारी कार्यालय में कलक्ट्रेट के कार्यरत कर्मचारियों के पदों को समाप्त किया जाए। विभाग के प्रस्तावित ढांचे में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के पदों को बढ़ावा जाए। आबकारी कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के कार्यों को मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाए। कर्मचारियों को राजकीय कार्य के लिए वाहन भत्ता दिया जाए।

ऋषिकेश नगरनिगम क्षेत्र में सूअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि

देहरादून (संवाददाता)। जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद देहरादून के ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सूअर पशुओं में अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग की पुष्टि होने के फ्लस्वरूप रोग की रोकथाम हेतु क्षेत्र को तीन भागों यथा इन्फेक्टेड जोन, सर्विलांस जोन, डिजीज फ्री जोन में विभाजित करने के आदेश दिए गए है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इन्फेक्टेड जोन ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रोग की पुष्टि हुई है, से एक कि0मी0 की परिधि को इन्फैक्टेड जोन घोषित किया गया है।

इस क्षेत्र में सूअर मांस /सुअर मास की दुकानो /सुअर आवगमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है। संक्रमित क्षेत्र एवं स्थानीय डिसइन्फेक्शन, फ्यूमिगेशन तथा टिक्स की रोकथाम के उपाय करने तथा रोगी पशुओं को स्वस्थ्य पशुओं से अलग रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इन्फैक्टेड जोन में आने वाले सूअर पशुओं की कलिंग करते हुए कार्कसंज को वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल किये जाने के निर्देश दिए गए है। सर्विलान्स जोन-इन्फेक्टेड जोन से 10 कि0मी0 की परिधि में आने वाले क्षेत्र को सर्विलान्स जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में भी सूअरों का आवगमन पूर्णतया वर्जित होगा ।

'बीज बम अभियान सप्ताह' का सीएम ने किया शुभारंभ

-पर्यावरण संरक्षण पर आधारित पुस्तक 'हिमालयी जन सरोकार' पुस्तक का किया विमोचन

'बीज बम अभियान सप्ताह' का शुभारंभ करते सीएम।

देहरादून (सू. वि.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में 'बीज बम अभियान सप्ताह' का शुभारंभ किया। हिमालय पर्यावरण जड़ी-बूटी एग्रो संस्थान 'जाड़ी' द्वारा यह बीज बम अभियान सप्ताह 09 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक चलाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित पुस्तक 'हिमालयी जन सरोकार' का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय पर्यावरण जड़ी-बूटी एग्रो संस्थान द्वारा द्वारिका प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में बीज बम अभियान की शुरूआत कर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। यह मानव एवं वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दिशा में सराहनीय कदम है। समय के साथ जैव विविधता प्रभावित हो रही है। जंगली जानवरों को जंगलों में खाद्य की उपलब्धता हो, इस दिशा में बीज बम अभियान एक अच्छा प्रयोग है। यह वैज्ञानिक तरीके से चलाया जा रहा अभियान है, जिसमें खर्चा भी बहुत कम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अभियान जन भागीदारी से ही बड़ा अभियान बनता है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान तभी सफल होते हैं, जब उनमें अधिक से अधिक जन सहभागिता हो। उन्होंने कहा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन कर क्या दे सकते हैं, इस बारे में सबको गम्भीरता से सोचना होगा एवं इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है।

इकोलॉजी के संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार अनेक कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड में सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) का आकलन किया जा रहा है।

राज्य सरकार इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में सामंजस्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2025 में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनायेगा। 2025 तक उत्तराखण्ड को विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विभागों, संस्थानों एवं सामाजिक क्षेत्र से लोगों द्वारा प्रदेश हित में क्या किया जा सकता है, इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्य के समग्र विकास के लिए विचारों की श्रृंखला 'बोधिसत्व' कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवियों के सुझाव लिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीज बम अभियान को व्यापक स्तर तक ले जाना होगा।

इस अवसर पर डॉ. मोहन सिंह रावत 'गांववासी', बीज बम अभियान के संस्थापक द्वारिका सेमवाल, पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज, मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी प्रशांत आर्य, कुलपति एस.जी.आर.आर यूनिवर्सिटी डॉ. यू. एस. रावत, प्रो. एम.एस.पंवार, प्रो. एम.एस.एम. रावत, डॉ. अरविन्द दरमोड़ा, एम्स ऋषिकेष से डॉ. संतोष, सावित्री उनियाल एवं वर्चुअल माध्यम से राज्य के विभिन्न जनपदों से जुड़े अधिकारी व इस अभियान से जुड़े लोग शामिल थे।

उत्तराखण्ड में गौशालाओं का अनुदान 5 गुना बढ़ा

-पशुपालन विभाग ने गौवंश रख रखाव के लिए 6 से बढ़ाकर 30 रूपये प्रतिदिन किया
-प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं 49 गौशाला

देहरादून (संवाददाता)। उत्तराखंड में गोवंश को बचाने के लिए भाजपा सरकार की तरफसे समय-समय पर विभिन्न निर्णय लिए जाते रहे हैं। राज्य में इसके लिए बकायदा गोवंश आयोग का भी गठन किया गया है। वहीं, अब गोवंश की रक्षा और बेहतर रखरखाव के लिए विभाग ने दिल खोलकर अनुदान देने का फैसला लिया है। इस दिशा में गौशालाओं के लिए रकम बढ़ाने के साथ ही कई नई योजना शुरू करने जा रही है। जिसके लिए पशुपालन विभाग की तरफसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दरअसल, उत्तराखंड गोवंश संरक्षण निधि की कार्यकारिणी समिति में वार्षिक बैठक की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गोवंश की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने का फैसला लिया है। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राज्य में रजिस्टर्ड गौशालाओं को अब तक दी जाने वाली रखरखाव के लिए अनुदान की राशि को 5 गुना तक बढ़ाया जाएगा।

बता दें कि राज्य में 49 रजिस्टर्ड गौशाला में हैं और इन्हें अब तक 6 रुपये प्रति गोवंश के लिहाज से अनुदान दिया जाता रहा है, लेकिन अब इस रकम को बढ़ाते हुए इसे 30 रुपये प्रति गोवंश करने का फैसला लिया गया है।

उधर, पशुपालन विभाग ने ग्राम गौ सेवक योजना को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत कुछ युवक मिलकर यदि गोवंश का रखरखाव करते हैं तो सरकार ऐसे युवकों को भी इस काम के लिए अनुदान देगी। इसके अलावा राज्य के सभी 13 जिलों को गोवंश की रक्षा के लिए करीब 12.5 लाख रुपए की रकम निर्गत करने का फैसला लिया गया है। इसके जरिए पुलिस समेत दूसरे संबंधित विभागों को गोवंश की रक्षा के लिए आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी। उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्गत मार्गदर्शी आदेशों के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ने दिनांक 11 नवम्बर, 2016 को निर्गत शासनादेश संख्या गृह अनुभाग-03 1930/आईआई (3)/ 2016-11(129)2016 के अनुरुप शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों ने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा भी निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने के लिए गोशाला शरणालयों व कांजी हाउसों का संचालन किया जाना अपेक्षित है। उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा इस कार्य के लिए गैरसरकारी संस्थाओं (मन्दिरों/मठों) से भी सहयोग लिये जाने की अपेक्षा की गयी है। पशुपालन विभाग द्वारा, उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के प्राविधानों के अनुरुप पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा, प्रदेश में अलाभकर गोवंश (निराश्रित, अनुत्पादक, वृद्ध, बीमार व गोतस्करों से जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश) को शरण दिये जाने के लिए गैरसरकारी पशुकल्याण संस्थाओं के माध्यम से कार्ययोजना संचालित की जा रही है। गतवित्तीय वर्ष में राज्यान्तर्गत 38 मान्यता प्रदत्त गोसदनों में कुल 9,482 अलाभकर गोवंशीय पशु शरणागत थे।

राज्य के मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को राजकीय अनुदान स्वीकृत किये जाने को गत 10 जून, 2022 को पशुपालन मंत्री की अध्यक्षता में राजकीय अनुदान चयन समिति की प्रथम बैठक आहूत की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि, कुल उपलब्ध बजट प्राविधान 83.33 लाख रुपये (रु0 02.44 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से राजकीय अनुदान) को गोवंश भरण-पोषण मद में सदुपयोग किये जाने के लिए सभी मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों में गत वित्तीय वर्ष में शरणागत गोवंश की औसत संख्या के सापेक्ष समानुपातिक आधार पर आबंटित कर दिया जाय। इस क्रम में उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रकरण शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

अखिल गढ़वाल सभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने देखी गढ़वाली फिल्म थोकदार

देहरादून(संवाददाता)। अखिल गढ़वाल सभा देहरादून के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा गढ़वाली फिल्म थोकदार देखने गए जिसमें सभा के अलग-अलग क्षेत्र (सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द, साकेत कॉलोनी अजबपुर कलां, एच एन बी बहुगुणा कॉलोनी, नेशविला रोड, नेहरू कॉलोनी, शिव कुंज केदारपुर, बंजारावाला, अपर राजीव नगर, जोगीवाला, इत्यादि) के सदस्यो द्वारा फिल्म देखी गई।

आज फिल्म के शो के शुभारंभ सभा के अध्यक्ष रोशन धस्माना महासचिव गजेंद्र भंडारी द्वारा की गई। सभा के अध्यक्ष रोशन धस्माना महासचिव गजेंद्र भंडारी ने सर्वप्रथम फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों को धन्यवाद दिया, उनकी अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, गढ़वाली भाषा के प्रति जो लगाव है उसी के फलस्वरूप हम सभी लोग यह फिल्म देख पा रहे हैं साथ ही हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं की अपनी संस्कृति, भाषा को जिंदा रखने के लिए हम सबको सभी गढ़वाली फिल्में देखनी चाहिए इससे पूर्व पिछले महीने सभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा खैरी के दिन गढ़वाली फिल्म भी देखी गई थी जिससे हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ता है और वह फिर निरंतर आगे भी अच्छा अभिनय करके समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। अखिल गढ़वाल सभा प्रदेश सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करती है कि अपनी संस्कृति, बोली, भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रीय फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यह फिल्म देख सके विशेषकर हमारे युवा जो अपनी संस्कृति, रीति, रिवाज के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं।

इस अवसर पर फिल्म के निर्देशक देबू रावत, मुख्य कलाकार राजेश मालगुडी, रणवीर सिंह चौहान, पन्नू गुसाईं, सभा के अध्यक्ष रोशन धस्माना, महासचिव गजेंद्र भंडारी, प्रचार सचिव अजय जोशी, दिनेश सकलानी, रीता भंडारी, विनोद सिंह चौहान, विजय सिंह चौहान, पंचम सिंह बिष्ट, कैलाश तिवारी, सुनील बडोनी, परिणीता बडोनी, मंगल सिंह, सोबन सिंह नेगी, रमेश कुमाई आदि उपस्थित थे।

गोदियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को निदेशक ने पुलिस को दी तहरीर

देहरादून (संवाददाता)। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मनोज पटवाल ने कहा जनता के साथ साथ पार्टी संगठन द्वारा भी पूरी तरह नकारे जाने तथा कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपनी अनर्गल बयानबाजी व झूठे आरोपों को लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं।

तहरीर देने वाले सहकारी बैंक के निदेशक मनोज पटवाल।

अपने पूरी तरह मिट चुके अस्तित्व बचाए रखने के लिए या चर्चाओं में रहने की कुंठा के चलते वह प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर आरोप लगाकर अपना छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं साथ ही घृणित राजनीति करके लोकतंत्र पर भी आघात कर रहे हैं।

इस तरह तरह की हरकतें लोकतंत्र में अक्षम्य में हैं। उन्होंने कहा कि गोदियाल द्वारा इस तरह के घृणित प्रयास बार-बार करने से अब स्थितियां बर्दाश्त से बाहर हो गई है।

पटेल नगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने हेतु उन्होंने तहरीर दी है।

उन्होंने कहा कि जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री होने के नाते बीकेटीसी के सदस्य ने डॉक्टर धन सिंह रावत से बीकेटीसी में श्री गोदियाल द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत की है तो इसमें बुरा क्या है।

प्रभारी मंत्री होने के नाते इस तरह घपलों घोटालों को खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना किसी भी राजनेता की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। कहा कि गणेश गोदियाल को क्षेत्र की जनता के साथ साथ उनकी कांग्रेस ने ही किक आउट कर दिया है। इससे साफहोता है कि वह आम जनता के तो क्या अपने पार्टी संगठन की भी किसी मतलब के नहीं है।

अनर्गल बयानबाजी और बेहूदा आरोप लगाने में उन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। कहां की एएनएम, आयुष्मान योजना व सहकारिता आदि से संबंधित जिन आरोपों का उपयोग गोदियाल खुद को चर्चाओं में रखने के लिए कर रहे हैं वह पूरी तरह से निराधार है।

समझ में नहीं आ रहा है कि चर्चाओं में रहने के लिए कांग्रेस का यह पिता मोहरा कितना नीचे गिरेंगे? दूसरे व्यक्ति की छवि को खराब करने का यह प्रयास अक्षम में है पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

स्वामी मुद्रक, प्रकाशक मोहन राजा द्वारा आर. के. प्रिन्टर्स 43/1, धर्मपुर माता मन्दिर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड से मुद्रित कराकर 95 बी शुभम विहार, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया

सम्पादक

मोहन राजा

फोन नं0- 01334-212184

Mob- 9997426600

कानूनी सलाहकार

एडवोकेट : के. पी. सिंह (देहरादून)

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून होगा

e-mail

kkalamkasauda@yahoo.in